2



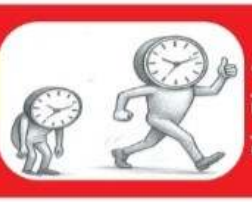
टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके किया घोटाला

5



राजनीति का शांत अनुभवी और संगठनात्मक नेता

7



अपडेट नहीं हुए तो आउटडेटेड हो जाओगे!

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 27 प्रति सोमवार, 23 नवंबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

पिता कमलनाथ के राजनीतिक मार्गदर्शन में नई भूमिका गढ़ रहे नकुलनाथ, हार के बाद भी जनता से नहीं टूटा संपर्क

भोपाल के दीपावली मिलन समारोह में समर्थकों ने 2028 के लिए जताई उम्मीद



कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

राजनीति में चुनावी हार किसी नेता की यात्रा का अंत नहीं होती, बल्कि कई बार वह नई शुरुआत का अवसर भी बनती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नकुलनाथ की मौजूदा सक्रियता को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भी नकुलनाथ ने क्षेत्र की राजनीति और जनता से अपने जुड़ाव को बनाए रखने की कोशिश जारी रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के राजनीतिक अनुभव और मार्गदर्शन के बीच नकुलनाथ अब अपनी अलग राजनीतिक भूमिका स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा की राजनीति का उल्लेख कमलनाथ के बिना अधूरा माना जाता है। लगभग चार दशकों से अधिक समय तक उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और स्थानीय राजनीतिक संगठन के विस्तार के माध्यम से उन्होंने छिंदवाड़ा में अपना मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया। यही कारण रहा कि छिंदवाड़ा लंबे समय तक कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गढ़ बना रहा। कमलनाथ इस लोकसभा क्षेत्र से नौ बार सांसद निर्वाचित हुए। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में बने संपर्कों ने छिंदवाड़ा को प्रदेश की राजनीति में विशिष्ट पहचान दिलाई। अब इसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नकुलनाथ के सामने है। वर्ष 2019 में छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रियता बनाए रखी। (शेष पेज 2 पर)





साय सरकार की पहल से कमार जनजाति के जीवन में आई खुशहाली

पीएम जनमन योजना बनी बदलाव का माध्यम, विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की इसी प्रतिबद्धता का सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। कभी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवनयापन करने वाले विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवारों के जीवन में अब बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। केंद्र और राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना इन परिवारों के लिए खुशहाली, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में इस दिशा में हो रहे कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि योजनाओं का प्रभाव अब उन बसाहटों तक भी पहुंच रहा है, जो लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रही हैं। पक्के मकान, बिजली, स्वच्छ पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, संचार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार से कमार जनजाति के परिवारों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है।
(शेष पेज 3 पर)



मप्र भाजपा के मीडिया प्रभारी से नहीं संभल रही जिम्मेदारी?

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे बृजगोपाल लोया

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश भाजपा में पद और जिम्मेदारी मिलने के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। खासकर मीडिया प्रभारी जैसा पद केवल संगठनात्मक सम्मान का विषय नहीं, बल्कि पार्टी की राजनीतिक छवि और सरकार की विश्वसनीयता से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रदेश भाजपा ने बृजगोपाल लोया को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर उनसे बेहतर मीडिया प्रबंधन की उम्मीद की थी। लेकिन इस नियुक्ति के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रदेश भाजपा का मीडिया विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पा रहा है? क्या पार्टी की बात प्रभावी ढंग से मीडिया और जनता तक पहुंच रही है? और क्या पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए विभाग के पास कोई प्रभावी व्यवस्था है? 23 सितंबर 2026 को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बृजगोपाल लोया को प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। इससे पहले यह जिम्मेदारी आशीष अग्रवाल के पास थी, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया विभाग में नई जिम्मेदारी मिली। (शेष पेज 6 पर)



स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ लगभग 500 करोड़ से अधिक का घोटाला

पढ़िए खुलासा पेज 2 पर

बाल शोषण के आरोपी पुरी को मप्र से राज्यसभा भेजकर क्या संदेश देना चाहती है भाजपा?

एपस्टीन फाइल्स की गूंज, राज्यसभा के फैसले से मध्यप्रदेश भाजपा में असंतोष

-विजया पाठक

पिछले दिनों मध्यप्रदेश में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद एक राज्यसभा सीट खाली हुई। इस सीट के खाली होते ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि इस बार किसी मध्यप्रदेश के नेता को ही यहां से चुनकर राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक बार फिर प्रदेश के नेताओं को ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसे नेता की मध्यप्रदेश में एंट्री करा दी है जिसके ऊपर बाल शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल केंद्रीय भाजपा ने बगैर सोचे समझे पूर्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने सत्ता से लेकर संगठन और प्रदेश के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद सभी अपना मन मसोस कर रह गए लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या किसी अन्य नेता और संगठन के पदाधिकारी में हिमाकत नहीं कि कोई इस बात का विरोध कर सके। (शेष पेज 3 पर)



उदय प्रताप सिंह के करीबी वीरेन्द्र तिवारी ने टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए दिया घोटाले को अंजाम

बच्चों की यूनिफॉर्म, स्कूल मेंटेनेंस से लेकर मशीनों की खरीदी तक में किया भ्रष्टाचार

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में सत्ता के गलियारों में सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें खूब होती हैं, लेकिन जब सरकारी विभागों के भीतर करोड़ों रुपये के घोटालों की परतें खुलने लगें तो इन दावों की असलियत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से सामने आए पांच गंभीर मामलों ने अब सीधे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि यह सभी घोटाले स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री उदय प्रताप सिंह के संरक्षण और उनके इशारे पर किये गये हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री सिंह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अफसर के साथ मिलकर इस पूरे मामले को रफा-दफा करने की सिफारिश करवाई लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मंत्री उदय प्रताप सिंह के इशारे पर हुए इस भ्रष्टाचार ने मोहन सरकार की छवि को दागी तो किया ही है साथ ही उन्होंने मोहन सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का भी मजाक बना दिया है।

दरअसल पिछले ढ़ाई वर्षों में मंत्री उदय प्रताप सिंह के इशारे पर स्कूल शिक्षा विभाग में अलग-अलग कार्यों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं। इनमें 149 करोड़ रुपये के स्कूल मेंटेनेंस घोटाले से लेकर 350 करोड़ रुपये की यूनिफॉर्म खरीदी, सांदीपनि स्कूलों के लिए करोड़ों के रसोई उपकरण, हजारों स्कूलों के बजट का हिसाब और पाठ्य पुस्तक निगम में कागज एवं प्रिंटिंग के टेंडर तक, शिकायत में अनियमितताओं पर पूर्व आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में शिकायत दर्ज कराते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

स्कूलों में काम कम, कागजों पर भुगतान ज्यादा?

सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। शिकायत के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 149 करोड़ रुपये के मेंटेनेंस कार्यों में गंभीर अनियमितताओं का आरोप है। मैहर जिले के रामनगर विकासखंड का मामला इस पूरे विवाद का उदाहरण बनकर सामने आया है। आरोप है कि भवन मरम्मत, पार्किंग शेड और साइकिल स्टैंड जैसे कार्यों के



लिए 4.37 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन जांच में 18 से अधिक स्कूलों में वास्तविक निर्माण कार्य नहीं होने की बात सामने आई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 17 दिसंबर को काम स्वीकृत हुआ, अगले ही दिन सामग्री की आपूर्ति शुरू हो गई और 30 दिसंबर से पहले काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकारी निर्माण कार्य इतनी जादुई गति से पूरे हो सकते हैं? क्या विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर काम का सत्यापन किया था? यदि जांच समिति ने अनियमितताओं की पुष्टि की थी तो फिर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

बच्चों के कपड़ों में भी टेंडर का खेल?

सरकारी स्कूलों के 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए करीब 350 करोड़ रुपये की निविदा ने दूसरा बड़ा विवाद खड़ा किया है। शिकायत में आरोप है कि टेंडर की शर्तें ऐसी बनाई गईं, जिनसे प्रदेश के स्थानीय उद्योगों, छोटे निर्माताओं, पावरलूम संचालकों, बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। 700 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली स्पिनिंग मिलों और 233 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले गारमेंट निर्माताओं जैसी शर्तों पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में मुंबई की मफतलाल कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया है।

रोटी बनाने की मशीन में भी भ्रष्टाचार

सांदीपनि स्कूलों के लिए 116 चपाती मेकर मशीनों की खरीदी का मामला भी कम चौंकाने वाला नहीं है। शिकायत के मुताबिक, एक मशीन की कीमत 07 लाख 74 हजार 842 रुपये स्वीकार की गई, जिससे कुल खरीदी करीब 8.98 करोड़ रुपये की होती है। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने डिंडोरी कलेक्टर द्वारा इसी प्रकार की मशीन लगभग 2 लाख 14 हजार रुपये में खरीदे जाने का दावा किया है। यही नहीं प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में आवंटित बजट का खर्च भी संदिग्ध है।

कागज और छपाई के टेंडर भी सवालों के घेरे में

पांचवां मामला पाठ्य पुस्तक निगम में कागज खरीदी और पुस्तकों की छपाई से जुड़े टेंडरों का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्रक्रियाओं में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। यह वह विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के लाखों बच्चों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की है। यदि यहां भी खरीदी और प्रिंटिंग के टेंडरों में गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह केवल वित्तीय अनियमितता का विषय नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है।

IAS अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. संजय गोयल, शिल्पा गुप्ता, विनय निगम, रोहित सिंह और हरजिंदर सिंह की भूमिका भी संदिग्ध है। यही नहीं सूत्रों के अनुसार मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह पूरा कारनामा उनके एक करीबी व्यक्ति वीरेन्द्र तिवारी के जरिए किया है, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग का बिचौलिया कहा जाता है। बताया गया है कि तिवारी ही वह शख्स है जिसके माध्यम से सभी टेंडरों में हस्तक्षेप किये जाते हैं और मनचाहे ढंग से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है

पिता कमलनाथ के राजनीतिक मार्गदर्शन में नई भूमिका गढ़ रहे नकुलनाथ, हार के बाद भी जनता से नहीं टूटा संपर्क

(पेज 1 का शेष)

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू से मिली पराजय ने नाथ परिवार के राजनीतिक प्रभाव के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। यह चुनाव केवल एक संसदीय सीट का परिणाम नहीं था, बल्कि छिंदवाड़ा की राजनीति में वर्षों से स्थापित समीकरणों में आए बदलाव का संकेत भी था।

हार के बाद भी जनता से संपर्क बनाए रखने की कोशिश

लोकसभा चुनाव में हार के बाद किसी भी नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने की होती है। नकुलनाथ के सामने भी यही चुनौती है। चुनावी परिणाम के बाद राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाने के बजाय वे छिंदवाड़ा के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वे अपने पिता के लंबे अनुभव से सीख लेते हुए क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर अपनी भूमिका विकसित कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के किसानों, युवाओं, आदिवासी समाज और आम नागरिकों से जुड़े सवालों को राजनीतिक विमर्श में बनाए रखना उनके सामने प्रमुख कार्यों में शामिल है। हालांकि चुनावी पराजय के बाद क्षेत्र में कांग्रेस के संगठन और पुराने राजनीतिक संपर्कों को फिर से मजबूत करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

भोपाल के दीपावली मिलन समारोह ने बढ़ाई राजनीतिक चर्चा

14 नवंबर 2026 को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर आयोजित दीपावली मिलन और जन्मदिन से जुड़े समारोह ने प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया। इस आयोजन में छिंदवाड़ा के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान नकुलनाथ के समर्थन में नारेबाजी हुई और कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनाने की मांग भी उठाई। समारोह के दौरान नकुलनाथ की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। समर्थकों की ओर से उनके पक्ष में नारे लगाए जाने को उनकी प्रदेशव्यापी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्पष्ट किया कि इसका निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और संगठन करेगा। उन्होंने छिंदवाड़ा को अपना पहला प्यार बताते हुए वहां के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। इससे प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व, संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

कमलनाथ का अनुभव नकुलनाथ के लिए राजनीतिक पूंजी

कमलनाथ का राजनीतिक सफर केवल छिंदवाड़ा तक सीमित नहीं रहा है। केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक उनका अनुभव व्यापक रहा है। वे कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों पर लंबे समय तक संगठन और सरकार में काम किया है। नकुलनाथ के लिए पिता का यह अनुभव निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ द्वारा वर्षों में तैयार किए गए सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को समझना तथा उन्हें नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ाना नकुलनाथ की राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हालांकि राजनीतिक विरासत अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं होती। जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए लगातार जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं का समाधान और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संवाद आवश्यक होता है। नकुलनाथ के सामने भी अपने पिता की पहचान के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान विकसित करने की चुनौती है।

2028 की तैयारी और कांग्रेस के सामने नई चुनौती

मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 में होना है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर चर्चाएं स्वाभाविक हैं। भोपाल के समारोह में नकुलनाथ के समर्थन में उठे नारों ने यह स्पष्ट किया कि उनके समर्थक उन्हें प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका में देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है। नकुलनाथ के लिए आने वाला समय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। उन्हें छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पुराने संगठन को मजबूत करने के साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता विकसित करनी होगी। किसानों, युवाओं, आदिवासियों और शहरी मतदाताओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी उनकी राजनीतिक यात्रा की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। राजनीति में जनता का विश्वास निरंतर प्रयासों से अर्जित होता है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में दशकों तक काम करके जो राजनीतिक आधार बनाया, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नकुलनाथ के सामने है। भोपाल का दीपावली मिलन समारोह उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और समर्थकों की अपेक्षाओं का एक सार्वजनिक मंच जरूर बना, लेकिन 2028 तक की राह संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और राजनीतिक प्रदर्शन की कसौटी पर तय होगी। फिलहाल यह स्पष्ट है कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा की राजनीति तक सीमित रहने के बजाय मध्य प्रदेश की व्यापक राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भूमिका बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में उनकी सक्रियता किस रूप में आगे बढ़ती है, इस पर प्रदेश की राजनीति की निगाहें रहेंगी।

पुरी से इस्तीफे के बजाय स्थानीय नेताओं का हक छीनकर दिया राज्यसभा सीट का ईनाम

(पेज 1 का शेष)

एपस्टीन फाइल में पुरी का नाम

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के बाद भारतीय राजनीति में भी सवालों का दौर शुरू हो गया है। मामला किसी सामान्य मुलाकात या औपचारिक परिचय का नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ ईमेल संवाद और बैठकों का है, जिसका नाम नाबालिगों के यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा रहा है। पुरी और एपस्टीन के बीच ईमेल संवाद के संदर्भ सामने आए हैं। सवाल यह है कि इस पूरे मामले में केंद्रित नेतृत्व ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्यों उन्होंने पुरी से इस पूरे मामले पर सफाई नहीं मांगी। जबकि उन पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें एक नए प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित करके इनाम दिया गया है।

स्थानीय दावेदारों के अरमानों पर फिरा पानी

मध्यप्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा भेजने का फैसला प्रदेश भाजपा के उन नेताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से दिल्ली तक अपनी राजनीतिक दावेदारी पहुंचाने की कोशिश में जुटे थे। राज्य में संगठन के लिए वर्षों से काम कर रहे कई नेताओं को उम्मीद थी कि राज्यसभा की सीट के जरिए उन्हें दिल्ली की राजनीति में जगह मिलेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस निर्णय से एक बार फिर यह संदेश गया है कि भाजपा में राज्यसभा की उम्मीदवारी का फैसला केवल स्थानीय समीकरणों और नेताओं की वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता। दिल्ली का नेतृत्व जब चाहे, किसी बाहरी चेहरे को प्रदेश के कोटे से संसद भेज सकता है। पार्टी के लिए यह रणनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन स्थानीय नेताओं के



मन में निराशा और असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। सवाल यह भी है कि जब मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार समर्पण की अपेक्षा की जाती है, तो राजनीतिक अवसरों के बंटवारे में उनकी दावेदारी कितनी मायने रखती है? क्या प्रदेश में योग्य और अनुभवी नेताओं की कमी है, या फिर दिल्ली का भरोसा स्थानीय नेतृत्व पर पूरी तरह कायम नहीं है? भाजपा नेतृत्व के लिए चुनौती अब स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालने की है। क्योंकि चुनाव केवल बड़े चेहरों से नहीं, बल्कि बूथ पर खड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते जाते हैं। दिल्ली का फैसला भले रणनीतिक हो, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश प्रदेश संगठन के भीतर दूर तक जाएगा।

नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किल

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर स्थानीय नेताओं की अनदेखी का मुद्दा अब संगठन के लिए नई चुनौती बन सकता है। हरदीप सिंह पुरी को प्रदेश से राज्यसभा भेजने के फैसले ने उन नेताओं की उम्मीदों को झटका दिया है, जो लंबे समय से संगठन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भले ही सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही जाए, लेकिन भीतरखाने की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इस असंतोष का असर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते। यहां स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर पर संगठन की एकजुटता निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि टिकट वितरण और राजनीतिक अवसरों में स्थानीय नेताओं को लगातार दरकिनार किया गया, तो उनकी निष्क्रियता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भाजपा का मजबूत संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन संगठन की मजबूती तभी कायम रहती है, जब समर्पित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अवसर मिले। दिल्ली के फैसले प्रदेश में लागू तो हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक परिणाम स्थानीय स्तर पर ही भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व नाराज नेताओं को मनाने में सफल होता है या यह असंतोष चुनावी मैदान में पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करता है।

पीएम जनमन योजना बनी बदलाव का माध्यम, विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार

(पेज 1 का शेष)

13 गांवों के 79 परिवारों तक पहुंचा विकास का लाभ

कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के अंतर्गत मावलीपारा, बिहावापारा, मारवाड़ी, धनोरा, सांईमुण्डा, मुसुरपुट्टा, दुधावा, बासनवाही, गंवरसिल्ली, भैंसमुण्डी, दलदली, बादल और डोमपदर सहित 13 गांवों में कमार जनजाति के 79 परिवार निवासरत हैं। इन परिवारों की कुल जनसंख्या 304 है। पहले इनकी आजीविका मुख्य रूप से बांस शिल्प और मजदूरी पर निर्भर थी। सीमित आर्थिक संसाधनों और आवागमन सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण इन परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब पीएम जनमन योजना के माध्यम से इन परिवारों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करना भी है।

पक्के आवास से बदली जीवन की तस्वीर

किसी भी परिवार के लिए अपना सुरक्षित घर होना सबसे बड़ा सपना होता है। कमार जनजाति के परिवारों के इस सपने को साकार करने में पीएम जनमन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अब तक 22 पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इससे इन परिवारों को कच्चे और असुरक्षित आवासों से निकलकर सुरक्षित घर में रहने का अवसर मिला है। योजना से लाभान्वित होने वालों में भैंसमुण्डी के इतवारूराम शोरी, मुसुरपुट्टा के पनकूराम मरकाम, सरजूराम मरकाम, प्रभुराम मरकाम, राजमन, राधुराम एवं सगराम शोरी, डोमपदर के मुकेश कुमार नेताम, दलदली की कमलाबाई कमार, मावलीपारा की देवलीबाई नेताम, मोतीलाल नेताम, लखनराम नेताम एवं अंजोरसिंह मरकाम तथा सांईमुण्डा के नवलसिंह शोरी, दुकाल नेताम एवं झनकीन नेताम सहित अन्य हितग्राही शामिल हैं। इन पक्के आवासों का निर्माण केवल भवन निर्माण तक सीमित उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे परिवारों को सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर जीवन परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं।

सड़क, बिजली और पेयजल से दूरस्थ गांवों को मिली नई पहचान

ग्रामीण विकास का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है, जब गांवों तक आवागमन, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। साय सरकार के प्रयासों के तहत पीएम जनमन योजना के माध्यम से इन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नल-जल योजना के माध्यम से घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, सड़क निर्माण से दूरस्थ बसाहटों का संपर्क आसपास के क्षेत्रों से बेहतर हुआ है। दलदली से कमारपारा दलदली, भीमापारा से बासनवाही के बाजारपारा, मावलीपारा के आवासपारा से कमारपारा तथा गंवरसिल्ली से खासपारा तक सड़क निर्माण कराया गया है। इन सड़कों से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ-साथ बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। सभी संबंधित गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मोबाइल टॉवर नेटवर्क की उपलब्धता से संचार व्यवस्था में भी सुधार आया है। अब इन क्षेत्रों के परिवार मोबाइल संचार के माध्यम से बाहरी दुनिया से अधिक सहजता से जुड़ पा रहे हैं।

स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान

किसी भी समाज के विकास का आधार स्वस्थ परिवार और शिक्षित नई पीढ़ी होती है। कमार जनजाति की बसाहटों में सभी गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण तथा अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल रही है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी बीमारियों की रोकथाम तथा जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

28 युवाओं को सरकारी नौकरी, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

कमार जनजाति के परिवारों को केवल बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि कमार जनजाति के 28 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। यह उपलब्धि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि रोजगार मिलने से युवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है और परिवारों की सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आता है। युवाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी से जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के सामने शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। इसके साथ ही पात्र परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन बैंक खाते, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं से जोड़ा गया है। इन दस्तावेजों और योजनाओं के माध्यम से परिवारों को सरकारी सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा हो रही है।

वन धन केंद्रों से आजीविका को मिलेगा प्रोत्साहन

कमार जनजाति की पारंपरिक आजीविका में बांस शिल्प और वन आधारित गतिविधियों का विशेष महत्व रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए वन धन केंद्र सरोना एवं नरहरपुर की निकटता का लाभ इन 13 बसाहटों के परिवारों को मिल रहा है। इससे वन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़ने और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आय बढ़ाने की संभावनाएं विकसित हो रही हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय परिवार अपनी पारंपरिक कला, कौशल और स्थानीय संसाधनों को आजीविका का मजबूत आधार बनाएं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ पारंपरिक ज्ञान और शिल्प को भी संरक्षण मिल सकता है।

समन्वित प्रयासों से जनजातीय विकास को नई गति

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए नौ केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय से 11 प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकास की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की जनजातीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता इन प्रयासों में परिलक्षित होती है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं का विस्तार यह दर्शाता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड में कमार जनजाति के परिवारों के जीवन में आ रहा बदलाव इसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण तस्वीर है। निश्चित रूप से 22 पक्के आवास, 28 युवाओं को सरकारी रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उत्साहजनक उपलब्धियां हैं। आने वाले समय में आजीविका के अधिक अवसर, शिक्षा की बेहतर सुविधाएं और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास इस बदलाव को और मजबूती दे सकते हैं। पीएम जनमन योजना ने यह साबित किया है कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन दूरस्थ और वंचित समुदायों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के सामने अब इस विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने और प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कमार जनजाति के परिवारों के जीवन में आ रही खुशहाली छत्तीसगढ़ में समावेशी और जनकल्याणकारी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

सम्पादकीय

बाजार की चमक फीकी या अर्थव्यवस्था के बदलते समीकरण?

भारत में सोना और चांदी केवल कीमती धातुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी सामाजिक परंपरा, पारिवारिक बचत और आर्थिक सुरक्षा के प्रतीक भी हैं। शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक और निवेश से लेकर संकट के समय तक इन धातुओं का विशेष महत्व रहा है। ऐसे में जब सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर इस गिरावट से क्या समझा जाए? क्या यह आम उपभोक्ताओं के लिए राहत का संकेत है, निवेशकों के लिए चेतावनी है या वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की आहट? पिछले कुछ दिनों में भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है। 20 नवंबर 2026 को सोने की कीमत में लगभग 4 प्रतिशत और चांदी में करीब 6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। इस वर्ष जनवरी में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद दोनों धातुओं में उल्लेखनीय सुधारात्मक गिरावट आई है। चांदी की कीमतों में गिरावट विशेष रूप से अधिक रही है। यह केवल भारतीय बाजार की घटना नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी कीमती धातुओं पर दबाव दिखाई दे रहा है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका की मौद्रिक नीति को लेकर बदलती उम्मीदें हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और वृद्धि किए जाने की आशंका ने निवेशकों की रणनीति बदल दी है। जब ब्याज दरें बढ़ने की संभावना होती है तो निवेशक सोने जैसी ऐसी संपत्तियों से दूरी बनाने लगते हैं, जिनसे नियमित ब्याज नहीं मिलता। इसके बजाय वे सरकारी बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि ने भी सोने-चांदी की चमक कम की है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में पिछले समय के दौरान तेजी से वृद्धि हुई थी। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों ने बाजार में पैसा लगाया था। अब कीमतों में गिरावट के बीच मुनाफावसूली और नुकसान से बचने की कोशिश में बिकवाली बढ़ी है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की नकदी संबंधी जरूरतों ने भी इस दबाव को बढ़ाया है। चांदी पर इसका असर अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उसका उपयोग आभूषणों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। वैश्विक औद्योगिक मांग को लेकर चिंता बढ़ने पर चांदी की कीमतें अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

भारतीय बाजार के संदर्भ में रुपये की विनिमय दर भी महत्वपूर्ण है। भारत सोने और चांदी का बड़ा आयातक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के साथ-साथ डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है। हाल के दिनों में रुपये की मजबूती ने घरेलू बाजार में गिरावट को और बढ़ाया है। इस परिस्थिति का सबसे प्रत्यक्ष लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है। जिन परिवारों में विवाह, त्योहार या अन्य सामाजिक अवसरों पर सोना-चांदी खरीदने की योजना है, उनके लिए कीमतों में कमी राहत का अवसर बन सकती है। आभूषण कारोबार को भी इससे मांग बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन निवेशकों के लिए तस्वीर इतनी सरल नहीं है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषकर वायदा कारोबार और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में निवेश करने वालों को बाजार की अस्थिरता को गंभीरता से समझना होगा। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या सोने की गिरावट का अर्थ उसकी सुरक्षित निवेश वाली पहचान समाप्त होना है? ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। सोना लंबे समय से महंगाई, मुद्रा संबंधी अनिश्चितता और भू-राजनीतिक संकट के समय निवेशकों के लिए सुरक्षा का माध्यम रहा है। केंद्रीय बैंकों की सोने में रुचि और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं इसके दीर्घकालीन महत्व को बनाए रख सकती हैं। वास्तव में सोने-चांदी की मौजूदा गिरावट हमें एक बड़ा आर्थिक संदेश दे रही है।

सियासी गहमागहमी

मुख्यमंत्री का विदेश दौरा रद्द, प्राथमिकता में विधानसभा या निवेश?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 24 नवंबर से प्रस्तावित सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का विदेश दौरा स्थगित होना राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से चर्चा का विषय है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल विदेश भ्रमण नहीं था, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं तलाशना और फरवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना था। मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर को स्पष्ट किया कि 7 से 11 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को प्राथमिकता देते हुए विदेश यात्रा स्थगित की गई है। जाहिर है, विधानसभा का सत्र किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है। विधायी कार्य, विपक्ष के सवालों के जवाब और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही सर्वोपरि है। लेकिन इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से सीधा संवाद जरूरी है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा का स्थगित होना निवेश संबंधी प्रयासों की गति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इसे निवेश नीति से पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने भूपेश बघेल को दिखाया आईना

छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका हमेशा प्रभावशाली रही है। लेकिन राजनीति में लंबा अनुभव और सत्ता का पूर्व गौरव ही किसी नेता की अंतिम ताकत नहीं होते, बल्कि संगठन का विश्वास और सहयोगियों का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की ओर से बघेल को आईना दिखाने की स्थिति पार्टी के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत मानी जा सकती है। दरअसल, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती इस समय केवल भाजपा से मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपने संगठन को मजबूत और एकजुट रखना भी है। यदि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचारों का टकराव सार्वजनिक होने लगे तो इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और जनता के बीच पार्टी की छवि पर पड़ता है। भूपेश बघेल प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। उनके कार्यकाल की उपलब्धियां और कमियां, दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी नेता आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता। कांग्रेस के भीतर से उठने वाली आवाजों को व्यक्तिगत विरोध मानने के बजाय आत्ममंथन का अवसर समझना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय स्थापित कर पाएगा? पार्टी को यह समझना होगा कि संगठन किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि सामूहिक नेतृत्व, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के भरोसे से मजबूत होता है। भूपेश बघेल के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है और कांग्रेस के लिए भी।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

मणिपुर में जहरीली शराब से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत दुखद है। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ।

यह हादसा नहीं, BJP सरकार की लापरवाही का नतीजा है। पहले हिंसा ने सैकड़ों घर उजाड़े, अब जहरीली शराब उजाड़ रही है - सरकार अब भी सो रही है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को पहले ही भ्रष्टाचार में अव्वल बना रखा है। लेकिन अब भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है।

पूरे प्रदेश में चल रहे पुलों और अन्य निर्माणों में जिस तरह से घटिया सरिया लगाया जा रहा है, उससे अब तक कई पुल गिर चुके हैं और आगे कमजोर पुलों का निर्माण जारी है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

मुकुल वासनिक: कांग्रेस की राजनीति का अनुभवी, शांत और संगठनात्मक नेतृत्व वाले नेता

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपनी पहचान किसी बड़े राजनीतिक विवाद या आक्रामक बयानबाजी से नहीं, बल्कि लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और निरंतर सक्रियता से बनाई है। मुकुल बालकृष्ण वासनिक कांग्रेस के ऐसे ही वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। चार दशकों से अधिक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल, कांग्रेस संगठन और संसद तक विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। मुकुल वासनिक का जन्म 27 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता बालकृष्ण रामचंद्र वासनिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय व्यक्तित्व थे। राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े मुकुल वासनिक को बचपन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रही। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में हुई। उन्होंने सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल तथा हिस्लोप कॉलेज, नागपुर से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं प्रबंधन की शिक्षा हासिल की। उनकी शैक्षणिक योग्यता में एम.ए. और एम.बी.ए. शामिल हैं।

मुकुल वासनिक के राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। वे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) से जुड़े और अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर वर्ष 1984 से 1986 तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इसके बाद वर्ष 1988 से 1990 तक भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने देशभर में युवाओं को कांग्रेस संगठन से जोड़ने और पार्टी की विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी राजनीतिक प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में अवसर प्रदान किया। वर्ष 1984 में वे महाराष्ट्र के बुलढाणा लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद निर्वाचित हुए। उस समय वे देश के सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल थे। उन्होंने आगे भी बुलढाणा का प्रतिनिधित्व किया और वर्ष 2009 में रामटेक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

मुकुल वासनिक ने अपने संसदीय अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 1993 से 1996 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने खेल एवं युवा मामलों तथा संसदीय कार्य से संबंधित मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2009 में केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार बनने पर उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2009 से 2014 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों तथा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़े विषयों पर कार्य किया। सामाजिक समानता और समावेशी विकास के मुद्दे उनके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष रहे हैं।

मुकुल वासनिक की पहचान केवल एक सांसद या पूर्व केंद्रीय मंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी रही है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। पार्टी के संगठनात्मक विस्तार, राज्यों में समन्वय और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रबंधन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन से जुड़े दायित्व भी उन्होंने संभाले हैं। वर्ष 2020 में कांग्रेस के उन 23 वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम भी शामिल था, जिन्होंने पार्टी में संगठनात्मक सुधार और पूर्णकालिक नेतृत्व की आवश्यकता को लेकर पत्र लिखा था। इसके बावजूद वे पार्टी की मुख्यधारा में सक्रिय रहे और संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते रहे। लोकसभा की राजनीति के बाद मुकुल वासनिक ने राज्यसभा में भी अपनी सक्रियता बनाए रखी। वे राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 5 जुलाई 2022 से उनका वर्तमान कार्यकाल प्रारंभ हुआ। संसद में वे विभिन्न राष्ट्रीय एवं सामाजिक विषयों पर अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। जून 2026 में उन्हें शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुकुल वासनिक का राजनीतिक जीवन धैर्य, अनुभव, संगठनात्मक दक्षता और निरंतर सक्रियता का उदाहरण है। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद तक पहुंचा है। उन्होंने कांग्रेस संगठन में विभिन्न उतार-चढ़ाव के बीच अपनी भूमिका बनाए रखी है। सार्वजनिक जीवन में अपेक्षाकृत शांत स्वभाव और पर्दे के पीछे रहकर संगठनात्मक कार्य करने की शैली उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनका स्थान उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और विभिन्न संवैधानिक एवं संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है।

हावड़ा स्टेशन पर स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान



-अमित राय

जगत प्रवाह. हावड़ा। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे की ओर से हावड़ा स्टेशन पर 'स्वच्छता से सुरक्षा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पाण्डेय, हावड़ा मंडल के डीआरएम विशाल कपूर और मशहूर पार्श्व गायिका उषा उत्थुप विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान हावड़ा मंडल के डीआरएम विशाल कपूर ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से पहले भी स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों विषयों को एक साथ जोड़कर अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि स्टेशन परिसर जितना साफ-सुथरा रहेगा, वहां दूश्यता उतनी ही बेहतर होगी। इससे आरपीएफ के जवानों को मानव तस्करी सहित अन्य छोटी-बड़ी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी। स्वच्छ स्टेशन न केवल यात्रियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करता है, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वच्छता और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित मशहूर गायिका उषा उत्थुप ने भी यात्रियों से रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने पूर्व रेलवे को लेकर एक विशेष गीत भी प्रस्तुत किया, जिसका इस्तेमाल रेलवे की ओर से जागरूकता अभियान के प्रचार-प्रसार में किया जाएगा।

स्कूटी और बाइक की भिड़ंत, एक युवक की मौत, चार घायल



-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। देवरी-घुघरी मार्ग पर स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार तीन युवक बारह गांव से तुलसी विवाह का सामान खरीदने देवरी आ रहे थे। वहीं स्कूटी पर एक युवती और पांच वर्षीय बच्ची सवार होकर बारह की ओर जा रही थीं। इसी दौरान दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऋषि पिता गोविंद आदिवासी की मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार राजा आदिवासी और अन्नू आदिवासी, दोनों निवासी बारह, गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूटी सवार रानी रैकवार निवासी रानीताल और पांच वर्षीय बच्ची भी हादसे में घायल हुई हैं। घटना की सूचना मिलने पर 112 की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल तीन वयस्कों को बेहतर उपचार के लिए सागर रेफर किया गया, जबकि पांच वर्षीय बच्ची का उपचार देवरी अस्पताल में जारी है। हादसे में शामिल मोटरसाइकिल का पंजीयन क्रमांक MP 15 MN 1120 और स्कूटी का पंजीयन क्रमांक MP 15 ML 8167 बताया गया है। घटना में एक युवक की असमय मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

सिवनी में खाकी पर गंभीर सवाल! होटल में ठहरे बालिग कपल को गांजे के झूठे केस में फंसाने की धमकी



-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. सिवनी। जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक होटल में ठहरे बालिग युवक-युवती को कथित तौर पर गांजे के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिवनी के एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा पुलिसकर्मियों के साथ होटल में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कथित तौर पर वे युवक के बैग में गांजा रखकर उसे फंसाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस की कार्यशैली, अधिकारों के दुरुपयोग तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सिवनी शहर के बाबरिया रोड स्थित सिद्धार्थ होटल का बताया जा रहा है। वायरल CCTV फुटेज कथित तौर पर 13 नवंबर 2026 का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम होटल पहुंची थी, जहां एक युवक और युवती साथ ठहरे हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। इस दौरान युवती ने कथित तौर पर बताया कि दोनों बालिग हैं, एक ही जाति से संबंध रखते हैं और आपसी सहमति से होटल में आए हैं। दोनों ने यह भी कहा कि वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी उन पर अपने माता-पिता को फोन कर होटल बुलाने का दबाव बनाते दिखाई देते हैं। जब युवती ने मोबाइल फोन अनलॉक करने और परिवार को बुलाने से इनकार किया, तो मामला और गंभीर हो गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया एक्शन

CCTV वीडियो वायरल होने और मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता दिखाई। पुलिस महानिदेशक की ओर से कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ASP दीपक मिश्रा, SDOP चंचलेश मरकाम समेत संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए।

परिजनों का आरोप, मौत का जिम्मेदार टिमरनी एसडीएम और रहटगांव तहसीलदार



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। मध्यप्रदेश में बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन और अव्वल आने की होड़ में क्या सरकारी कर्मचारियों से उनकी निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम लिया जा रहा है? क्या अधिकारियों के निर्देशों के सामने कर्मचारियों के परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया है? रहटगांव तहसील से सामने आया मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। टिमरनी अनुविभाग के कर्मचारियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि कर्मचारियों से निर्धारित कार्यालयीन समय के बाद भी देर रात तक काम कराया जा रहा है। यहां तक कि शनिवार, रविवार और अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यालय बुलाकर काम करवाने की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार अतिरिक्त कार्य के दबाव से उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब एक कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत का उल्लेख किया गया। ज्ञापन के अनुसार, 17 नवंबर 2026 की रात रहटगांव तहसील कार्यालय से अपने घर लौटते समय ऑपरेटर वैदेह वर्मन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आवेदन में इस घटना को देर रात तक काम करने की परिस्थितियों और कर्मचारियों की सुरक्षा से जोड़ते हुए चिंता जताई गई है।

कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि शासन द्वारा कार्यालयीन कार्य का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों से इस समय-सीमा के बाद भी काम लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शनिवार और रविवार जैसे साप्ताहिक अवकाश के दिनों में भी कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहकर काम करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है।कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि जब शासन ने कार्यालयीन समय निर्धारित कर रखा है तो फिर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से देर रात तक काम कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या प्रशासनिक लक्ष्य और बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों पर डालकर अधिकारियों की जवाबदेही समाप्त हो जाती है? कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, आयुक्त नर्मदापुरम संभाग और कलेक्टर हरदा को भी भेजी है। ज्ञापन में छह प्रमुख मांगें रखी गई हैं।

चक्रवात से प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी राज्य सरकारः मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अकवान चक्रवात के कारण फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार हर प्रभावित किसान के साथ खड़ी है। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवात से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण कराकर सभी पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत पात्रतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की फसलें बीमित हैं, उन्हें संबंधित फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र बीमा दावा राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की भेंट, लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर हुई चर्चा

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान तथा पूर्व में लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से बनबसा बैराज एवं नगरा बाईपास नहर की मरम्मत तथा इनकैया पुल एवं सूखा पुल सहित सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले पुराने एवं जर्जर पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण का विषय उठाया। उन्होंने इन कार्यों को जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनबसा बैराज एवं नगरा बाईपास नहर की मरम्मत तथा संबंधित पुलों का सुदृढ़ीकरण स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों एवं किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने परिसंपत्तियों से जुड़े विभिन्न मामलों के समाधान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से जनहित से जुड़े विषयों का समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

(पेज 1 का शेष)

लोया प्रदेश प्रवक्ता और सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को संगठन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा।

मप्र भाजपा के मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया से नहीं संभल रही जिम्मेदारी?



इतनी बड़ी टीम, फिर भी समन्वय की चुनौती क्यों?

02 अप्रैल 2026 को भाजपा ने प्रदेश मीडिया विभाग की बड़ी टीम घोषित की थी। इसमें 33 प्रदेश प्रवक्ता, 41 मीडिया पैनलिस्ट और 09 सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए थे। यानी पार्टी के पास मीडिया में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद हैं। मीडिया प्रभारी की भूमिका केवल यह तय करने तक सीमित नहीं हो सकती कि किस प्रवक्ता को किस टीवी चैनल की बहस में भेजना है। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रवक्ता जिस विषय पर बोल रहा है, उसके पास सही आंकड़े और अधिकृत जानकारी हो। यदि सरकार की किसी योजना पर सवाल उठते हैं तो संबंधित विभाग से तथ्य जुटाकर प्रवक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार और संगठन के बीच संवाद की कड़ी कहां है?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के सामने कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं। कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर लगातार सवाल उठते हैं। इन मुद्दों पर मीडिया विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उसे सरकार की उपलब्धियों को सामने रखने के साथ जनता की शिकायतों और विपक्ष के आरोपों पर भी तथ्यात्मक जानकारी जुटानी चाहिए। सवाल यह है कि क्या मीडिया विभाग के पास सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों के साथ समन्वय की कोई व्यवस्थित व्यवस्था है? क्या किसी विवाद के सामने आने पर संबंधित विभाग से तत्काल जानकारी प्राप्त की जाती है? क्या पत्रकारों को आधिकारिक जवाब उपलब्ध कराने की समय-सीमा तय है? यदि इन व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं किया गया तो मीडिया विभाग के सामने केवल बयान जारी करने की औपचारिकता रह जाएगी। इसकी निष्क्रियता की पूरी जिम्मेदारी केवल लोया की है।

लोया की निष्क्रियता से सरकार और पार्टी को नुकसान

बृजगोपाल लोया की निष्क्रियता के कारण वर्तमान में सरकार और संगठन की छवि को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जनता के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रदेश की मीडिया प्रबंधन निष्क्रिय है। वह अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है। आज पार्टी और सरकार की जो किरकिरी हो रही है उसके लिए केवल लोया ही जिम्मेदार हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश का मीडिया प्रबंधन इतना कमजोर नजर आ रहा है।

पत्रकारों का भरोसा जीतना भी बड़ी जिम्मेदारी

मीडिया प्रभारी और पत्रकारों के बीच संवाद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पत्रकारों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराना और उनके सवालों का जवाब देना मीडिया विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन लोया के समय में ऐसा नहीं हो रहा है। मीडिया से संवाद केवल औपचारिक बचा है। पत्रकारों से संवाद नहीं होगा तो सरकार या पार्टी की छवि कैसे निखर पायेगी। इससे पहले भी प्रदेश में मीडिया का प्रबंधन होता था, पत्रकारों से समन्वय होता था। लोया कम से कम उसी परिपाटी पर चलते तो बेहतर होता। आज पत्रकारिता का स्वरूप बदल चुका है। डिजिटल मीडिया की तेजी के कारण गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है।

आशीष अग्रवाल ने बेहतर साधा था मीडिया प्रबंधन

पिछले 10 साल से मध्यप्रदेश में मीडिया प्रबंधन का काम आशीष अग्रवाल संभाल रहे थे। अब वह दिल्ली चले गये तो उनकी जगह पर ही लोया आये हैं। आशीष अग्रवाल के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वह मीडिया संस्थानों और पत्रकारों से बेहतर तालमेल बिठाकर रखते थे। मेल-मिलाप करते थे। केवल प्रेस-नोट बनाने तक सीमित नहीं रहते थे। उनके समय सरकार की छवि को भी निखारा जाता था। खासकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की छवि को तो बेहतर बनाकर रखा जाता था। आज वह स्थिति नहीं है। लोया के समय में तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की भी किरकिरी हो रही है।

प्रदेश अध्यक्ष को करनी चाहिए मीडिया विभाग की समीक्षा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लोया की नियुक्ति के बाद मीडिया और सोशल मीडिया विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया था। 26 सितंबर को पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी संगठन की नीतियों और सरकार की योजनाओं को व्यापक स्तर तक पहुंचाने की अपेक्षा व्यक्त की गई थी। अब समय है कि प्रदेश संगठन मीडिया विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बृजगोपाल लोया अपनी घोषित प्राथमिकताओं को जमीन पर कितना उतार पाए हैं?

अपडेट नहीं हुए तो आउटडेटेड हो जाओगे!

आज की बात



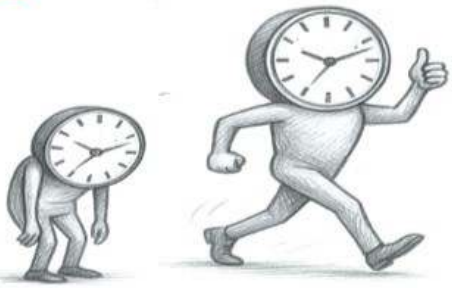
प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

वक्त के साथ जो बदले, वही अपनी पहचान बनाएगा,
जो कल में ही उलझा रहा, उसका आज भी खो जाएगा।

कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति वर्षों से पूरी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी कर रहा है। अचानक उसे बताया जाता है कि अब उसकी जगह नई तकनीक काम करेगी। एक व्यापारी की दुकान कभी ग्राहकों से भरी रहती थी, आज ऑनलाइन बाजार ने उसकी बिक्री घटा दी है। एक शिक्षक वर्षों से उसी पद्धति से पढ़ा रहा है, जबकि उसके विद्यार्थी उससे कहीं आगे की डिजिटल दुनिया में पहुँच चुके हैं। सवाल यह नहीं कि ये लोग मेहनती नहीं थे, सवाल यह है कि दुनिया बदलती रही और क्या इन्होंने खुद को बदला? यही आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। मौसम बदलते हैं, नदियाँ रास्ते बदलती हैं और समय अपनी दिशा बदलता है। फिर मनुष्य पुरानी सोच, आदतों और तरीकों से चिपका रहकर आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है? याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं, बल्कि अप्रासंगिक हो जाना है। क्योंकि समय किसी को बाहर नहीं करता, समय के साथ न बदलने की जिद उन्हें बाहर कर देती है।

बदलाव विकल्प नहीं, अस्तित्व की जरूरत

अंग्रेजी में कहते हैं- "Change is the only constant." अर्थात परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। विंडबना देखिए, हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना नहीं भूलते, लेकिन अपनी सोच और क्षमताओं को वर्षों तक पुराने संस्करण में चलाते रहते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक नौकरियों से लेकर कारोबार तक की



तस्वीर बदल रहे हैं। अब प्रतिस्पर्धा केवल अनुभव की नहीं, सीखने की गति की है। भारतीय संस्कृति भी परिवर्तन की प्रेरणा देती है। गुरुकुल से आधुनिक विश्वविद्यालय तक की यात्रा इसका प्रमाण है। जड़ों से जुड़े रहकर नई शाखाएँ फैलाना ही वास्तविक विकास है।

युवाओं की असली डिग्री है निरंतर सीखना

आज डिग्री अवसर दिला सकती है, लेकिन सफलता के लिए नई तकनीक, रचनात्मक सोच, संवाद कौशल और व्यावहारिक समझ जरूरी है। अंग्रेजी में कहते हैं- "Learn, unlearn and relearn." अर्थात नया सीखिए, पुरानी अनुपयोगी धारणाएँ छोड़िए और फिर सीखिए। भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल इंसान और मशीन में नहीं, बल्कि तकनीक अपनाने और उससे पिछड़ने वालों के बीच भी होगी। जो सीखना छोड़ देता है, वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है।

बदलाव से इनकार, भविष्य से इनकार

कभी फोटोग्राफी की दुनिया पर राज करने वाली कोडक डिजिटल बदलाव के साथ अपना व्यवसाय नहीं ढाल सकी और संकट में पड़ गई। संदेश स्पष्ट है - कल की सफलता, कल की सुरक्षा नहीं है। व्यापारी को ऑनलाइन बाजार, डिजिटल भुगतान और ग्राहकों की बदलती जरूरतें समझनी होंगी। नौकरीपेशा व्यक्ति को नई दक्षताएँ, शिक्षक को आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ और डॉक्टर, किसान, पत्रकार सहित हर पेशेवर को अपने क्षेत्र के नए ज्ञान से जुड़ना होगा। अनुभव तभी ताकत है, जब उसमें नया ज्ञान जुड़ता रहे।

अपना प्लान-B तैयार रखिए!

आज छँटनी केवल कमजोर कर्मचारियों की समस्या नहीं, अनुभवी और कुशल पेशेवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में नौकरी बचाने के लिए अपनी उपयोगिता बढ़ाइए और नौकरी जाने की स्थिति के लिए विकल्प तैयार रखिए। अपने क्षेत्र की नई तकनीक सीखिए, एक अतिरिक्त कौशल विकसित कीजिए और आय के वैकल्पिक स्रोत तलाशिए। कम से कम छह महीने के आवश्यक खर्चों का आपातकालीन कोष बनाइए। अपना प्रोफेशनल नेटवर्क मजबूत रखिए और नए अवसरों पर नजर रखिए। अंग्रेजी में कहते हैं- "Don't put all your eggs in one basket." अर्थात अपनी सारी उम्मीदें एक ही सहारे पर मत टिकाइए। याद रखिए, बैकअप प्लान बनाना असफलता का डर नहीं, भविष्य के प्रति समझदारी है। असली अपग्रेड वही है, जो आपको संकट आने से पहले तैयार कर दे।

तकनीक ही नहीं, रिश्ते भी अपडेट कीजिए

कई परिवार इसलिए बिखरते हैं क्योंकि पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, लेकिन संवाद का तरीका नहीं बदलता। माता-पिता बच्चों की सोच नहीं समझते, बच्चे बुजुर्गों के अनुभव को अनदेखा करते हैं। रिश्तों में संवेदनशीलता, व्यवहार में लचीलापन और निर्णयों में विवेक भी जरूरी है। भारतीय संस्कृति का संदेश 'चरैवेति-चरैवेति' अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहो, इसी जीवनदृष्टि का प्रतीक है। अपडेट होने का अर्थ संस्कार छोड़ना नहीं, संस्कारों के साथ समझ विकसित करना है। हर समस्या का समाधान बदलाव नहीं, लेकिन बदलाव के बिना अनेक समस्याओं का समाधान कठिन है। प्रतिदिन पूछिए- आज नया क्या सीखा, क्या सुधारा और कल के लिए कितना तैयार हुआ? याद रखिए, जो खुद को अपडेट करते हैं, वे भविष्य बनाते हैं; जो बदलाव से मुँह मोड़ते हैं, वे अतीत बन जाते हैं। फैसला आपका है- अपडेट होना है या आउटडेटेड हो जाना है।

भारत की बारहमासी नदियाँ अब मौसमी नदियों की तरह व्यवहार कर रही हैं

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

नदियाँ किसी देश की जीवनरेखा होती हैं। वे केवल पानी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि कृषि, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, संस्कृति और पारिस्थितिकी का आधार भी हैं। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और साल भर बहती हैं, चाहे गर्मी हो या बारिश इसलिए इन्हें बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। ये नदियाँ हमारी संस्कृति, कृषि और जीवन का आधार रही हैं। लेकिन आज की वास्तविकता चिंताजनक है। अनेक नदियों का प्रवाह कम हो गया है, गर्मियों में उनकी धारा लगभग समाप्त हो जाती है और वे मौसमी नदियों की तरह व्यवहार करने लगी हैं। गंगा , ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली छोटी नदियों में पानी की कमी दर्ज की गई है। यह सिर्फ पानी की कमी नहीं, बल्कि पारिस्थितिक संकट की चेतावनी है। आईआईटी गांधीनगर ने नदियों के आधार प्रवाह यानी बेसफ्लो का 60 वर्षों के डाटा का अध्ययन करते हुए 18 प्रमुख नदी घाटियों के 227 निगरानी केंद्रों का विश्लेषण किया, जिसमें करीब 30 फीसदी केंद्रों पर नदियों के बेस फ्लो में बड़ी कमी दर्ज की गई। बारहमासी नदियों और मौसमी नदियों में अंतर समझना आवश्यक है।

बारहमासी नदियाँ वर्षा, हिमनदों के पिघलने और भूजल से निरंतर जल प्राप्त करती हैं। इसलिए उनका बहाव गर्मियों में भी बना रहता है। इसके विपरीत, मौसमी नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं। वर्षा के बाद उनमें पानी बढ़ता है, पर गर्मी में वे सूख जाती हैं। भारत की कई मैदानी नदियाँ, जैसे गोमती, रामगंगा, चंबल, केन और बेतवा, अपना प्रवाह मुख्य रूप से वर्षाजल और भूजल के आधार प्रवाह से पाती हैं। जब भूजल गिरता है या वर्षा अनियमित होती है, तो इन नदियों का बहाव बाधित हो जाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत की अनेक नदियों का पानी पूरे वर्ष समान रूप से नहीं बहता, बल्कि कुछ स्थानों पर गर्मी में नदी लगभग सूख जाती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, भारत की प्रमुख नदी घाटियों में आधार प्रवाह में गिरावट के पीछे भूजल का अत्यधिक दोहन, भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु संबंधी कारक संभावित रूप से जिम्मेदार हैं। भूजल का अनियंत्रित दोहन बड़ा कारण है। सिंचाई, घरेलू उपयोग और उद्योगों के लिए ट्यूबवेलों से भारी मात्रा में भूमिगत जल निकाला जाता है। जब भूजल स्तर नदी के तल से नीचे चला जाता है, तो नदी का पानी भूमि में रिसकर भूजल को पोषित करने के बजाय उसमें सोखा जाने लगता है। इस प्रकार नदी अपना आधारभूत प्रवाह खो देती है। हरित क्रांति के बाद सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग तेजी से बढ़ा। पंपों और बोरिंग तकनीक ने गहराई तक पानी निकालना संभव बनाया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि जमीन के नीचे का जल संचय घट गया। वर्षा का पानी जब ठीक से जमीन में नहीं रिसता, तो भूजल रीचार्ज नहीं होता। परिणामस्वरूप नदियाँ बारिश के मौसम में भरती हैं, पर बारिश खत्म होते ही सूखने लगती हैं। इसके अलावा कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बारिश का समय बदल गया है। दूसरा कारण है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। जंगल कम होने से भूजल स्तर घटा है और नदियों को पानी देने वाले झरने सूख गए हैं। नदियों पर बड़े-बड़े बाँध और अत्यधिक रेत खनन, जिससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। इसके अलावा शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। नदियों का जीवन केवल उनके किनारों तक सीमित नहीं है। उनका असली जीवन उनके जलग्रहण क्षेत्र, जंगलों, पहाड़ों, झरनों, तालाबों और दलदलों में बसता है। जंगल वर्षा के पानी को धीरे-धीरे जमीन में सोखते हैं, जिससे वह भूजल बनता है और बाद में नदियों को पोषित करता है। लेकिन अत्यधिक कटान, अवैध खनन, शहरीकरण और वृहद निर्माण कार्यों ने इन क्षेत्रों को कमजोर कर दिया है। जब जंगल कटते हैं, तो वर्षा का पानी जमीन में नहीं रिसता, बल्कि तेजी से बहकर निकल जाता है। इससे बाढ़ की संभावना बढ़ती है, पर सूखे के समय नदियों में पानी कम रह जाता है। इस प्रकार एक ही जल प्रणाली दो तरफ से प्रभावित होती है। बरसात में बाढ़ और गर्मी में सूखा। यही कारण है कि अनेक नदियाँ अब "बारहमासी" नाम के बावजूद मौसमी होती जा रही हैं। बांध, नहरें और जल विचलन परियोजनाएँ सिंचाई, बिजली और जलापूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पर उनके असंतुलित उपयोग ने नदियों के स्वाभाविक बहाव को बाधित किया है। बड़े बांधों द्वारा पानी को रोकने और नहरों के माध्यम से वितरित करने से नदी के निचले हिस्सों में प्रवाह घट जाता है। कृषि, उद्योग और शहरों के लिए जल का अत्यधिक आवंटन भी नदियों को कमजोर बनाता है। कावेरी और कृष्णा जैसी नदियों की स्थिति इसका स्पष्ट उदाहरण है। कावेरी कई गर्मियों में कई स्थानों पर सूखी पाई गई है, जबकि कृष्णा नदी का प्रवाह लगातार घट रहा है। गोदावरी भी पहले तेलंगाना का बारहमासी जलस्रोत मानी जाती थी, पर अब उसका अस्तित्व संकट में है। यह दर्शाता है कि समस्या केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। हिमालयी नदियों को हिमनदों के पिघलने से अतिरिक्त जल मिलता है, पर जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे से दीर्घकालिक जल सुरक्षा खतरे में है। पहले जहाँ हिम पिघलने से गर्मियों में भी नदियों को पानी मिलता था, वहीं अब यह संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए हिमालयी नदियों की स्थिति भी पहले जैसी सुरक्षित नहीं है। इस संकट से निपटने के लिए केवल बड़ी परियोजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं। सबसे पहले भूजल के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण चाहिए। सिंचाई में टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी जल-बचत तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। वर्षाजल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम और जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से भूजल रीचार्ज बढ़ाया जा सकता है।

नदियों को उनके प्राकृतिक बहाव का अधिकार देना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि बांधों और नहरों से पानी निकालने के बाद भी नदी में इतना पानी छोड़ा जाए कि वह जीवित रह सके। नदी तटों पर अतिक्रमण हटाना, सीवेज शुद्धिकरण सुनिश्चित करना और औद्योगिक कचरे पर कड़ा नियंत्रण लगाना आवश्यक है। भारत की बारहमासी नदियों का मौसमी नदियों में बदलना एक गंभीर पारिस्थितिक चेतावनी है। यह केवल नदियों की समस्या नहीं, बल्कि कृषि, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, जैवविविधता और मानव जीवन की समस्या है। यदि भूजल का दोहन, जंगलों की कटाई, प्रदूषण और अनियोजित विकास जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियाँ केवल नक्शों में दिखने वाली रेखाएँ बन जाएँगी। इसलिए नदी संरक्षण को केवल सरकार का कर्तव्य नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व मानना होगा। इस समस्या का समाधान हमारे हाथ में है। हमें वृक्षारोपण करना होगा, जल का संरक्षण करना होगा, नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना होगा और "जल ही जीवन है" के मंत्र को अपनाना होगा। यदि हमने अभी भी नदियों को नहीं बचाया, तो आने वाली पीढ़ी को नदी केवल किताबों में ही देखने को मिलेगी।

सुशासन के संकल्प से

नवा रायपुर बन रहा

एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

NSTI
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

NIELIT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

NMIMS
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

NIFT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



NFSU
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस

R.O. No. : 14133/ 1





श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक। RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)